and (c). On resumption depends upon the nature of clarifications needed by the Central Water Commission and the speed with which these are furnished by the State Governments concerned.

from Delhi Development Authority the land was proposed to be handed over to MCD on 5-11-82 but the same could not be done because on actual survey it was revealed that there is a little variation in the size of the plot allotted and at site. L & DO has been directed to hand over the possession of the actual area, forthwith to the M.C.D.

Clearance of Modernisation Schemes for Irrigation by CWC

1240. SHRI M. V. CHANDRASHE-KHARA MURTHY: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

- (a) whether the Central Water Commission has received for approval schemes for modernisation of irrigation;
- (b) if so, wheather 38 modernisation schemes have been approved by Government;
- (c) if so, whether these will bring irrigational benefits to 1.61 million hectares of land; and
- (d) by what time Government are likely to clear the projects which have been waiting for Centre's clearance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHR1 RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir.

- (b) and (c) Out of 38 modernisation schemes received in the Central Water Commission, 7 schemes have been approved for implementation. 7 schemes will bring irrigation benefit to 0.53 million hectares.
- (b) The modernisation schemes proposed by the various States involve complex technical issues and large outlays and therefore the Central Water Commission has to carry out a detailed technical examination before acceptance by the Planning Commission. The time required for clearance

ग्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम, 1981

1241. श्री मूलचन्द डागा: क्या खाद्य ग्रीर नागरिक पूर्ति मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ग्रावश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1981 को क्रियान्वित करने के लिए हाल ही में एक सितम्बर, 1982 को ग्राधिसुचित किया गया है ;
- (ख) क्या चीर बाजारी का रोकथाम तथा भ्रावश्यक वस्तुभ्रों की सप्लाई बनाये रखना ग्रधिनियम, 1980 को हाल ही में बनाया गया है ;
- (ग) यदि हां, तो इन कानुनों के अन्तर्गत पृथक-पृथक दायर किए गए मामलों की रा यवार संख्या कितनी है; ग्रौर
- (घ) इन कानूनों के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ग्रौर उनके ग्रन्तर्गत कितने व्यक्तियों की दंडित किया गया है ?

ख द्य ग्रीर नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भ गवत झा द्वाजाद): (क) से (घ) ग्रावश्यक वस्त् (विशेष उपबन्ध) ग्रिधिनियम, 1981, 1-9-1982 को सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों (ग्रण्डमान तथा निकोबार द्वीप समह. ग्ररुणाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली, लक्ष द्वीप द्वीप-समूह तथा मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़ कर) में श्रिधसूचित किया गया है। चोर बाजारी निवारण तथा ग्रावश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश श्रक्तूबर, 1979 में प्रख्यापित किया गया था ग्रीर बाद में फरवरी;

176

1980 में इसे संसद् के भ्रधिनियम का रूप दिया गया था । चीर बाजारी निवारण तथा ग्रावश्यक वस्तु प्रदाय ग्रधिनियम, 1980 के तहत इस ग्रधिनियम के जारी किए जाने की तारीख से लेकर 15-2-83 तक जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के ग्रादेश जारी किए गए उनके बारे में की गई कार्रवाई तथा जिन्हें रिहा भ्रादि किया गया उनकी संख्या

के बारे में राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है जहां तक म्रावश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) म्राध-नियम 1981 के अन्तर्गत की गई कारंबाई के ब्यौरे का सम्बन्ध है, सूचना एकत की जा रही है ग्रीर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

चोर बाजारी निवारण तथा ग्रावश्यक वस्तु प्रदान ग्रधिनियम, 1980 के ग्रन्तर्गत, इस ग्रिधिनियम के जारी किए जाने की तारीख से लेकर 15.2.83 तक जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के ग्रादेश जारी किए गए तथा जिन्हें रिहा ग्रादि किया गया, उनकी संख्या के बारे में राज्यवार सूचना।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या जिन की नजरबंदी	9	फरार	नजर- बंद			
	के भ्रादेश दिए गए	राज्य	मंडल	लय के			
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रान्ध्र प्रदेश	19	1	3	12	+(3)*	-	शून्य
श्रसम	1	1			antina companii	—	शून्य
बिहार 🖟	34	_	9	4	5+(5)*	9	2
गुजरात े	126	14	53	45	3	3	8
हिमाचल प्रदेश	4	4	_				शून्य
कर्नाटक	58	22	7	27	1	1	शून्य
मध्य प्रदेश	79	12	9	15	11+(13)*	13	6
महाराष्ट्र	65	1	8	30	22	-	4
उड़ीसा	28	12	10	1	2+(1)*		2
पंजाब	14	-		4	10	and an extension of	शून्य

177 Written Answers	FILA	LOUINI	J, 1204	(JAKA)	And of the Pro- this		-/~
1	2	3	4	5	6	7	8
रःजस्थान	5		1	1	3		शून्य
उत्तर प्रदेश	147	45	32	23	28	14	5
ग्रहणाचल प्रदेश	1	-	1		inequilibries.		शून्य
दिल्ली	18	8	9	1			शून्य
योग	599	120	142	163	85(22)*	40	27

PHALGUNA 9 1904 (SAKA) Written Answers 178

(* कोष्ठक में दिए गये ग्रांकड़े उन व्यक्तियों के हैं, जिन्हें उक्त तारीख से छ: महीने ग्रयवा उससे काफी पहले नजरबन्द किया गया था तथा जिन्हें ग्रव तक रिहा कर दिया गया होगा, लेकिन जिनके रिहा किए जाने के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से ब्यौरा ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुग्रा है।)

Construction of Houses in Cooperative Sector

1242. SHRI RAM PYARE PANIKA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

- (a) whether Government propose to speed up and encourage construction of houses in cooperative sector;
- (b) if so, the number of cooperative societies registered at present;
- (c) whether Government propose to allot land to all the registered cooperative societies;
 - (d) if so, by what time; and
 - (e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRIBUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

- (b) According to the National Cooperative Housing Federation, the number of such Societies is estimated to be 35,000.
- (c) to (e) Housing is a State subject and land to Cooperative Housing So-

cieties is allotted by State Governments and their agencies. However, the Working Group on Private Housing set up by the Ministry of Works & Housing has, inter-alia recommended that lands at pre-determined rates should be earmarked for housing cooperative societies. The State Governments have been requested to initiate appropriate action.

National Welfare Fund for Fishermen

1243. SHRI K.A. RAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) whether the National Association of Fishermen has suggested a National Welfare Fund for fishermen;
 - (b) if so, the details thereof; and
 - (c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF AGRICUL-TURE (RAO BIRENDRA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) It has been proposed that a minimum cess of 10 per cent on the total foreign exchange earned by the export of marine fishery products be imposed for creation of a National Wel-